

## देश की सक्षिप्त खबरें

नितिन गडकरी ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना



मुंबई, 10 नवम्बर 2024(ए)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने दागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बार दागी नेताओं को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे उनकी ही पार्टी के कुछ लीडर नाराज हो सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भ्रष्ट नेताओं के शामिल होने पर दो टूक अंदाज में अपनी राय रखी है। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद गडकरी ने कहा कि जैसे-जैसे फसल बढ़ती है, इसके साथ बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। उन्होंने भाजपा के वैचारिक आदर्श को बचाए रखने पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'बीजेपी का विस्तार हो रहा है और हमारे पास बहुत सारी फसलें हैं। इनमें से कुछ फसलें ऐसी हैं, जो बहुत अच्छे हैं और कुछ अपने साथ बीमारियां भी लाती हैं।'

डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूं..



बुर्का पहनी लड़की ने किया दावा, मचाई हलचल

नई दिल्ली, 10 नवम्बर 2024(ए)। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब दुनिया को उनके अगले कदमों की उम्मीद है। ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान युद्ध खत्म करने से लेकर अवैध आप्रवासियों को बाहर निकालने समेत कई दावे किए थे। इन सबसे के बीच ट्रंप से जुड़ा एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है। वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है, जिसमें बुर्का पहनी एक महिला दावा कर रही है कि वह ट्रंप की सगी औलाद है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

मुंबई पुलिस ने पकड़ी करोड़ों के चांदी की ईट



मुंबई, 10 नवम्बर 2024(ए)। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के शोर के बीच मुंबई के विक्रोली में कैश वैन से साढ़े छह टन की चांदी की ईटें जब्त की गई हैं। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विक्रोली पुलिस और चुनाव आयोग की जांच टीम की ओर से जब्त की गई कैश वैन में चांदी की ईटें मिली हैं। करोड़ों रुपये की कीमत वाली ये चांदी की ईटें ब्रिक्स कंपनी की गाड़ी से मुलुंड के एक गोदाम में रखी गई थीं। चांदी की ये ईटें किसकी हैं, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है।

## बुलडोजर एक्शन को लेकर आ गया फैसला

करने होंगे ये जरूरी काम, वरना चलेगा सुप्रीम कोर्ट का डंडा...

नई दिल्ली, 10 नवम्बर 2024(ए)। यूपी सरकार के जिस बुलडोजर एक्शन को कई राज्यों की सरकारों ने फॉलो किया उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता है। एपेक्स कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा, कानून के शासन में 'बुलडोजर न्याय' पूरी तरह अस्वीकार्य है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि बुलडोजर के जरिए न्याय करना किसी भी न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता।

राज्य सरकारों को बुलडोजर चलाने से पहले करने होंगे ये 6 काम

कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार द्वारा इस तरह की मनमानी और एकतरफा कार्रवाई को बंद नहीं किया जा सकता। अगर इसकी अनुमति दी गई, तो

अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक मृत पत्र में बदल जाएगी। सीजेआई के रिटायरमेंट की पूर्व संस्था पर शनिवार को अपलोड किए गए एक विस्तृत आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय निर्धारित करते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया है कि किसी भी विध्वंस से पहले उचित सर्वेक्षण, लिखित नोटिस और आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक आरोप दोनों का सामना करना पड़ेगा।

अदालत ने किसी भी संपत्ति को ढहाने से पहले छह आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया। पहला- अधिकारियों को सबसे पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और मानचित्रों को सत्यापित करना होगा। दूसरा- नंबर पर उन्हें वास्तविक अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए उचित सर्वेक्षण करना होगा। तीसरा- कथित अतिक्रमणकारियों को तीन लिखित नोटिस जारी किए जाने चाहिए। चौथा- उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद एक्शन का स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए। पांचवां- अतिक्रमणकारियों को स्वीच्छक रूप से



कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन हो: सुप्रीमकोर्ट

सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, बुलडोजर के जरिए न्याय का ऐसा वाक्या कहीं और सामने नहीं आया। यह एक गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा उच्चस्तरीय और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाएगी, तो नागरिकों की संपत्तियों का विध्वंस बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में होगा।

अपना अतिक्रमण हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए और नंबर छह- अगर जरूरी हो तो अतिरिक्त भूमि

कानूनी रूप से अधिग्रहित की जानी चाहिए। उसके बाद ही कोई अन्य बड़ा एक्शन लेना चाहिए।

बेंच ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कानून के शासन में बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।

क्या है 300 ए?

300 ए के प्रावधानों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 300 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। टॉप कोर्ट ने 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक मकान को ध्वस्त करने से संबंधित मामले में छह नवंबर को अपना फैसला सुनाया। बेंच ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को अंतरिम उपाय के तौर पर याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। आपको बताते चलें कि याचिकाकर्ता का मकान एक सड़क परियोजना के लिए ढहा दिया गया था।

## महाविकास अघाड़ी ने जारी किया घोषणा पत्र



युवाओं और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

मुंबई, 10 नवम्बर 2024(ए)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें राज्य की जनता को पांच प्रमुख गारंटीयों का भरोसा दिया गया है। घोषणापत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने

का वादा किया गया है। इसके साथ ही, कांग्रेस ने 50वें आरक्षण की सीमा हटाने का भी ऐलान किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कहा कि महाविकास अघाड़ी की ये पांच गारंटीयें राज्य के हर नागरिक के कल्याण के लिए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी योजनाओं के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। महालक्ष्मी योजना के तहत, सभी

महाविकास अघाड़ी की पांच गारंटी महालक्ष्मी योजना:

महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता। महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा। समानता की गारंटी- जातिगत जनगणना कराने का वादा। आरक्षण की 50वें सीमा हटाने का संकल्प। कुटुंब रक्षा- 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा। मुफ्त दवाओं की सुविधा। कृषि समृद्धि- किसानों का 3 लाख रुपये तक कर्ज माफ। नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन। युवाओं को वचन- बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपये की सहायता।

महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी और महाराष्ट्र की महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। खड़गे ने किसानों के लिए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का वादा भी किया, बशर्ते कि वे समय पर कर्ज चुकाते हों। महिलाओं को साल में छह

रियायती गैस सिलिंडर दिए जाएंगे, जिनकी कीमत 500 रुपये होगी। इसके अलावा, महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव महाराष्ट्र के भविष्य को बदलने के लिए है। महाविकास अघाड़ी ने अपने कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों के चुकाते हों। महिलाओं को साल में छह

## कनाडा में मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

खालिस्तानी आतंकी पत्र का बेहद करीबी निकला आरोपी

नई दिल्ली, 10 नवम्बर 2024(ए)। कनाडा में मंदिर पर हमला करने के मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान ब्राम्पटन के 35 वर्षीय इंदरजीत गोसाल के रूप में हुई है। वह मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड है और खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पत्र का करीबी है। ग्रेटर टोरंटो में हिंदू मंदिर पर हमले का प्लान इंदरजीत ने ही तैयार किया था। इंदरजीत गोसाल सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पत्र का दाहिना हाथ है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद वही रेफरेंडम से जुड़े काम को देख रहा



है। पुलिस ने बताया, गोसाल को 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है। उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है और कहा गया कि तय तारीख पर कोर्ट में हजरत होना है। 4 नवंबर को खालिस्तानियों ने कनाडा में कई मंदिरों को निशाना बनाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन हमलों की निंदा करते हुए कनाडा को कड़ा संदेश दिया था। कनाडा में हिंदुओं पर इस तरह के हमले को लेकर दुनिया के कई देशों ने निंदा की थी।

## दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल

नई दिल्ली, 10 नवम्बर 2024(ए)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मुताबिक रविवार को दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले एक व्यापारी से सरेआम रंगदारी मांगी गई। भाजपा से दिल्ली की कानून-व्यवस्था ही नहीं संभल रही है, तो जनता पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी उसे कैसे दे दे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी के ही विधायक और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने

इस पर कहा कि दिल्ली में रविवार को सुबह-सुबह फिर एक व्यापारी से रंगदारी मांगे जाने की खबर आई है। कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है, जब दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से सरेआम गोलीबारी या रंगदारी मांगने की खबर न आ रही हो। गैरस्टॉर्स के नेटवर्क को बचाने के चक्कर में भाजपा ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था का बेड़ा गंका कर दिया है। इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी गई। अगर भाजपा से कानून-व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दे।

## चुनावी मंच से नितिश कुमार ने दहाड़ मारी

अभी चुपचाप सुनो, ज्यादा मत बोलिए...

गया, 10 नवम्बर 2024(ए)। बिहार के मुखिया नितिश कुमार आज रविवार को गया के इमामगंज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान नितिश कुमार जब मंच से अपनी उपलब्धियां

गिनवा रहे थे, सभा में मौजूद जीविका दीदियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पर नितिश कुमार भड़क गए और उन्हें चुप रहने को कहा। दरअसल, गया के इमामगंज के जमुना टांड मैदान में एनडीए के हम प्रत्याशी दीपा मांझी के समर्थन में रविवार को सीएम नितिश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे। जहां चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। नितिश कुमार के भाषण



के दौरान जीविका दीदियों ने अपनी मांगों को लेकर शोर मचा रही थीं। जीविका दीदी अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर बोलने लगीं। तभी नितिश कुमार ने कहा, -अभी

चुपचाप सुनो, आपकी बात को सुनेंगे, ज्यादा मत बोलिए। उसी का जवाब देते हुए मंच से सीएम नितिश कुमार ने जीविका दीदियों को कहा कि सुनो स्वयं सहायता समूह पहले कितना कम था। जीविका दीदियों को लेकर और क्या कहा?

2006 कर्ज लेकर जीविका के स्वयं सहायता का वृद्धि कराया। केंद्र वाला पहले जीविका को जीविका दीदी पर नाराज था। उन लोगों ने देखकर आजीविका किया है। 1 करोड़ 31 लाख जीविका दीदियों की संख्या है। अब यह शहरी क्षेत्रों में भी होगा। पंचायती राज में महिला को 50वें आरक्षण दिया। पुलिस में 35वें आरक्षण दिया। यह सबसे ज्यादा आरक्षण सिर्फ बिहार में है। अगला चुनाव के पहले 12 लाख को नौकरी मिलेगी।

## कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए बड़ी मुश्किलें

फास्ट-ट्रैक वीजा किया गया समाप्त...

अब वीजा महीनों में मिलेगा... नई दिल्ली, 10 नवम्बर 2024(ए)। भारतीय छात्रों को कनाडा में पढ़ाई करने का सपना पूरा करने में अब और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कनाडा सरकार ने 2018 से लागू किए गए 'स्ट्रैटेजिक डायरेक्ट स्ट्रीम' प्रोग्राम को बंद करने का ऐलान किया है, इसके चलते अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए फास्ट-ट्रैक वीजा अध्यायन परमिट

प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इससे छात्रों को तेजी से वीजा मिलने में मदद मिलती थी। पहले जहाँ स्टडी वीजा की प्रक्रिया 6 हफ्तों में पूरी हो जाती थी, अब इसमें कई महीने लग सकते हैं। इस फैसले से भारतीयों समेत 14 देशों के छात्रों को बड़ा झटका लगा है। खासकर पंजाब राज्य के करीब 50,000 छात्रों को इससे परेशानी हो सकती है, जो पहले इस प्रोग्राम के तहत कनाडा जा रहे थे। 2022 में कनाडा पढ़ने गए 80 प्रतिशत भारतीयों ने इस प्रोग्राम के जरिए वीजा हासिल किया था।

वीजा प्रक्रिया में आएं बदलाव

अब छात्रों को स्टडी वीजा के लिए स्ट्रैटेजिक एप्लिकेशन प्रोसेस के तहत आवेदन करना होगा, जिसमें 4 से 6 महीने या उससे अधिक का समय लग सकता है। इसके अलावा वीजा रिजेक्शन की संभावना भी बढ़ सकती है। एसडीएम प्रोग्राम के तहत रिजेक्शन रेट 10 प्रतिशत से भी कम था, जबकि सामान्य प्रक्रिया में यह 25 प्रतिशत तक हो सकता है।



एसडीएम प्रोग्राम को बंद करने के पीछे कारण

कनाडा सरकार का कहना है कि सभी

कनाडा के प्रधानमंत्री का खालिस्तान मुद्दे पर बयान

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने 8 नवंबर को यह स्वीकार किया कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये लोग पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा में कई हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, लेकिन वे भी पूरे कनाडाई हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ट्रुडो के इस बयान से भारत के उन आरोपों को बल मिला है कि कनाडा सरकार खालिस्तानी समर्थकों को संरक्षण दे रही है।

मिल जाता था, लेकिन अब सरकार ने आवास की कमी और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या को देखते हुए इस प्रोग्राम एक फास्ट-ट्रैक वीजा प्रोसेस था, जिससे छात्रों को सिर्फ 20 दिनों में वीजा

नए स्टडी परमिट की सीमा तय की है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य प्रोग्राम्स को भी कवर करेगी। आने वाले समय में वीजा प्रोसेस और भी सख्त होने की संभावना है।

संपादकीय

सिख अलगाववादियों पर हमले बेतुका और निराधार

सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कनाडाई मंत्री के आरोपों को बेतुका और निराधार' करार देते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया गया और उन्हें एक नोट सौंपा गया जिसमें कनाडाई मंत्री के आचरण पर नाराजगी जताई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नोट में भारत सरकार ने कनाडा के उपमंत्री डेविड मॉरिसन के आरोप पर गहरी नाराजगी जताई। मॉरिसन ने एक संसदीय पैनल के समक्ष कहा था कि कनाडा में सिख अलगाववादियों पर हमले की साजिश के पीछे पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के एक शीर्ष पदस्थ अधिकारी थे। दरअसल, कनाडा पुलिस ने जब से खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर भारत सरकार के एजेंटों का नाम लिया है, तब से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास उभर आई है। कनाडा पुलिस ने कहा है कि उसकी जांच में कनाडा में हत्याओं और हिंसक कृत्यों और भारत सरकार के एजेंटों के बीच संबंधों का पता चलता है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते दोनों ने एक दूसरे के राजनयिकों को वापस बुला लिया। कनाडा तनाव बनाए रखने का रवैया अपनाए हुए है, और बीते मंगलवार को कनाडाई मंत्री का बयान इसी सिलसिले का हिस्सा है। कनाडा आखिर, भारत के साथ संबंधों की कीमत पर इस प्रकार का रवैया क्यों अपनाए हुए है। दरअसल, कनाडा में निकट भविष्य में चुनाव होने हैं, और वहां सिखों की खासी आबादी है, जिस पर अलगाववादी खासा प्रभाव रखते हैं। इनके मतों पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नजर है। इसलिए इन मतदाताओं के तुष्टिकरण की गरज से कनाडा गैर-जिम्मेदाराना हरकत किए जा रहा है। सबूत मांगे जाने की भी अनदेखी कर रहा है। राजनयिक परिपाटियों का धोरा उल्लंघन करने तक से नहीं चूक रहा। उसने भारत को साइबर खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची तक में डाल दिया है। कनाडा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को ऑडियो और वीडियो निगरानी में रखकर उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया है। वह हर वो कोशिश कर रहा है जिससे भारत के खिलाफ वैश्विक विमर्श पैदा करने वाले देशों को भी आरोप लगा रहा है, उसके समर्थन में कोई प्रमाण भी पेश नहीं कर रहा। कहा जा सकता है कि कनाडा के व्यवहार में परिपक्वता का अभाव है।

महिलाओं के लिए खतरा बनी साइबर की दुनिया



-प्रियंका सौरभ आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)

**इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली स्त्रियों की बढ़ती तादाद एक सकारात्मक बदलाव है। लेकिन, इसने और अधिक संख्या में महिलाओं को वचुअल दुनिया में खतरों के जोखिम में डाल दिया है। हॉ, ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के प्रति ऑनलाइन अपराध की घटनाएँ बढ़ रही हैं। इनमें यौन उत्पीड़न, धमकाने, डराने बलात्कार या जान से मार देने की धमकियाँ देने, साइबर दुनिया में पीछा करने और बिना सहमति के तस्वीरें और**

**वीडियो शेयर करने जैसी वारदातें शामिल हैं। सर्व में पता चला है कि 60 प्रतिशत लड़कियों और महिलाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्पीड़न का सामना किया है और इनमें से लगभग 20 प्रतिशत ने इसके चलते या तो सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया या फिर उसका इस्तेमाल कम कर दिया।**

इसी तरह यून विमेन ने पाया है कि दुनिया भर में 58 प्रतिशत महिलाएँ और लड़कियों को किसी न किसी तरह के ऑनलाइन शोषण का शिकार होना पड़ा है। इनमें ट्रोल्सिंग, पीछा करने, डॉक्सिंग और लैंगिकता पर आधारित दूसरे तरह के ऑनलाइन हिंसक बर्ताव हैं, जो डिजिटल युग के नए खतरों के तौर पर उभर रहे हैं। ऑनलाइन इंटेलिजेंस का उपयोग डीपफेक वीडियो और चित्र बनाने के लिए किया जा रहा है, जो महिलाओं को मनागढ़त सामग्री के साथ लक्षित करते हैं जो अक्सर प्रकृति में यौन या मानहानिकारक होती हैं। यू.एस। की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए अपने अभियान के दौरान झूठे और हानिकारक संदर्भों में उद्धे चित्रित करने वाले डीपफेक का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन इंटेलिजेंस टूल महिलाओं के चरित्र और विश्वसनीयता को कम करने के लिए डिजाइन की गई झूठी कथाएँ या स्त्री-द्वेषी सामग्री फैलते हैं, विशेष रूप से नेतृत्व की भूमिकाओं



में महिलाओं को लक्षित करते हैं। रिपब्लिकन प्राइमरी के दौरान निक्की हेली हेरफेर की गई छवियों और फुजी खबरों का शिकार हुई। महिलाओं को ऑनलाइन वस्तुकरण और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का असंगत स्तर का सामना करना पड़ता है, जो वास्तविक नकली सामग्री बनाने की ऑनलाइन इंटेलिजेंस क्षमता द्वारा बढ़ाया जाता

करने और हटाने के लिए उन्नत ऑनलाइन इंटेलिजेंस डिटेक्शन सिस्टम में निवेश करना चाहिए। मेटा (फेसबुक) ने हाल ही में डीपफेक से निपटने के लिए ऑनलाइन इंटेलिजेंस टूल की घोषणा की, लेकिन उनका कार्यान्वयन असंगत बना हुआ है। प्लेटफॉर्म को स्पष्ट जवाबदेही उपाय प्रदान करने चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए कि वे अपनी मॉडरेशन नीतियों के पारदर्शी ऑडिट के साथ फ्लैग की गई सामग्री को कैसे संभालते हैं। यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम (2022) में डिजिटल प्लेटफॉर्म को सामग्री मॉडरेशन क्रियाओं की रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है।

प्रदान करने चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए कि वे अपनी मॉडरेशन नीतियों के पारदर्शी ऑडिट के साथ फ्लैग की गई सामग्री को कैसे संभालते हैं। यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम (2022) में डिजिटल प्लेटफॉर्म को सामग्री मॉडरेशन क्रियाओं की रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है। तकनीकी कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि लिंग पूर्वाग्रह कम हो और हानिकारक उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन इंटेलिजेंस टूल का दुरुपयोग रोका जा सके। गूगल ऑनलाइन इंटेलिजेंस सिद्धांत ऑनलाइन इंटेलिजेंस के जन्मदाता उपयोग पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन अधिक कार्यान्वयन की आवश्यकता है। सरकारों को डेटा सुरक्षा कानूनों को लागू करना चाहिए और डीपफेक-विशेष कानूनों सहित एआई-जनरेटेड सामग्री के दुरुपयोग को सम्बोधित करने के लिए विशिष्ट कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 सामग्री मॉडरेशन के

जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी का निर्वाह

चौदहवाँ लोक सभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि संसद का बहिष्कार करने वाले सांसदों का दैनिक भत्ता काट लिया जाना चाहिए। आपको शायद ज्ञात हो कि लोक सभा सत्र के दौरान मात्र एक मिनट की कार्यवाही पर सदन का खर्चा लगभग ढाई लाख रुपए आता है। चटर्जी का मानना था कि ऐसे कानूनी प्रावधान या नियम तय किया जाना चाहिए जिनसे सांसद सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए। पर अफसोस है कि इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर तब से अब तक ऐसा कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। निस्संदेह यह गंभीर समस्या है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चाहे वे सांसद हो या विधायक अक्सर सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह गंभीरता से नहीं करते। वैसे तो सांसदों के आचरण से शुब्ध हो कर तत्कालीन दिवंगत लोक सभाध्यक्ष जीएमसी बालयोगी ने भी यह मांग उठाई थी और कुछ सख्त कार्यवाही पर सहमति भी बनी थी पर उसे लागू करने में विभिन्न पार्टी नेताओं की आनाकानी से उसमें वे सफल नहीं हो पाए थे, परंतु इस मुद्दे पर यदि गंभीरता से सभी पार्टी नेता अपना

सहयोग सांसदों के आचरण के सुधार की पहल में करते हैं तो कोई कारण नहीं जो लोक सभा की कार्यवाहियों के समय को जाया जाने से बचाया न जा सके। अगर ऐसा लोक सभा में हो जाता है तो इससे सीख लेकर प्रदेश सरकार अपने-अपने विधानसभाओं में विधायकों को सांसदों के आचरण का अनुसरण जैसी सीख देने में सफल हो सकते हैं वरना जनता के खून-पसीने की कमाई को यू ही जनसेवक बर्बाद करते रहेंगे और जनता यू ही देखती रह जाएगी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां सांसदों के आचरण के कारण कई लोक सभा सत्र के दौरान हो-हल्ला मचने से बर्बाद हुए। अब आप समझ सकते हैं कि मात्र एक मिनट लोक सभा कार्यवाही का खर्चा जब ढाई लाख रुपए आता है तो बीते लोक सभा सत्रों के दौरान इतने समय की कीमत से अगर विकास कार्य होता या किसानों के कर्ज को माफ किया गया होता तो आए दिन कर्ज के कारण देश जिस प्रकार किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनमें से कुछ को अवश्य ही बचाया जा सकता है। अगर तर्फ तो कर्ज और भुखमरी के कारण लोग असमय मर रहे हैं और दूसरी ओर समय की कीमत को

न समझना यह समझदारी कर्तई नहीं हो सकती। कुछ वर्ष पहले पत्रकार सूर्य प्रकाश ने सांसदों के व्यवहार पर एक शोध किया। अनेकों सांसदों से बातचीत के आधार पर उन्होंने अंग्रेजी में अपनी पुस्तक स्टाट एक्स इंडियन पार्लियामेंट-विधेयकों पर चर्चा की खानापूर्ति हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि अनेक सांसदों की रुचि संसद की कार्यवाही में नहीं होती और वे अपनी उपस्थित रजिस्टर पर दस्तखत करके सत्र के दौरान सदन से गायब रहते हैं, बल्कि निहित स्वार्थों का हित पूरा होता है। पिछले एक दशक में उजागर हुए अनेक किस्म के घोटालों से बहार हुए सांसदों के चरित्र और कार्य शैली पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं, जिनका यहाँ खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इस सब के बावजूद यह जरूरी है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चाहे वे सांसद हों या विधायक सदन के प्रति जिम्मेवारी से व्यवहार करें और इसके लिए कानून और नियमों में आवश्यक सुधार किए जाएं। सांसदों को अनुशासित करने की दृष्टि से लोक सभा अध्यक्ष को यह पहल करनी ही चाहिए और हर दल के अध्यक्ष को इस प्रयास में सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और विधायिका के प्रति जनता में विश्वास बढ़ेगा। जब सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों और निजी क्षेत्र में लगे लोगों से अनुशासित आचरण की अपेक्षा की जाती है और जरा सी लापरवाही पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है तो फिर सांसदों और विधायकों से ऐसे आचरण की अपेक्षा क्यों न की जाए। कहवत भी है कि यथा राजा तथा प्रजा। सांसदों और

विधायकों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। निजी जीवन में न सही पर कम से कम सदन में तो उसकी मर्यादा के अनुरूप आचरण किया ही जाना चाहिए। जो भी सांसद या विधायक सदन की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद भी उपस्थित न रहे उनका दैनिक भत्ता तो काटा ही जाए लगातार तीन बार ऐसा करने पर संसदीय समितियों से हटा दिया जाए और इसके बावजूद उनका व्यवहार को बदले तो दिल्ली में दी गई उन्हे आवास या अन्य सुविधाएं वापस लेने की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। कुल मिलाकर प्रयास यही होना चाहिए कि सांसद और विधायक सदन के सत्र के दौरान जिम्मेदारी से व्यवहार करें, जिससे जनता की आस्था उनमें बढ़े। जो भी लोक सभा अध्यक्ष, जब भी ऐसा प्रयास करे, तो ऐसे प्रयास का मुक्त हृदय से समर्थन किया जाना चाहिए। पूरे देश के जागरूक नागरिकों विशेषकर युवाओं को ऐसे प्रयास के समर्थन में अध्यक्ष को पत्र भी लिखने चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़े।

**कविता मजिल से नजरें हटाना नहीं**

**घटती-घटना**  
श्याम सुंदर साहू  
राजिव गान्धियावट्ट छत्तीसगढ

कितना भी मुश्किल हो डार सफर में तुम डर जाना नहीं सफलता पाना है तुम्हें अगर मजिल से नजरें हटाना नहीं सीखना है अपने गलतियों से कोशिश करना छोड़ना नहीं लड़ते रहना है चुनौतियों से मजिल से नजरें हटाना नहीं। हालातों से तुम लड़ते रहना इन हालातों से घबराना नहीं लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना सांसद और विधायक सदन के सत्र के दौरान जिम्मेदारी से व्यवहार करें, जिससे जनता की आस्था उनमें बढ़े। जो भी लोक सभा अध्यक्ष, जब भी ऐसा प्रयास करे, तो ऐसे प्रयास का मुक्त हृदय से समर्थन किया जाना चाहिए। पूरे देश के जागरूक नागरिकों विशेषकर युवाओं को ऐसे प्रयास के समर्थन में अध्यक्ष को पत्र भी लिखने चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़े।

रेलवे के खोखले दावे

संजय गोस्वामी मुंबई, महाराष्ट्र

भारतीय रेल जैसे पहली सरकार में थी वैसा ही हाल आज भी है पहले ज्यादा पारदर्शिता थी अब ऑनलाइन इ टिकट बुकिंग का खामियाजा जनता को भुगतना पर रहा और उसका अब लागत मूल्य से रेवेन्यू को जोड़कर आई आर आर यानि भाड़ा लागत मूल्य यानि इलेक्ट्रिक, डीजल, मेटेनेंस और मैनपावर को लागत मूल्य में 50कम यानि नुकसान ही दिखाया जा रहा है। अक्सर पर्व त्योहार में तो और ही लूटा जा रहा है जैसे आप सुपर तत्काल लेते हैं तो करीब करीब हजार का ही व्यय होता है प्लेटफॉर्म की स्थिति जस की तस है पर्व में भीड़ में लोग रेलवे की लापरवाही से भगदड़ मच रहा है और लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं एक मित्र ने बताया की स्पेशल ट्रेन में पर्व के लिए ट्रेन पकड़ा और करीब 38घंटे का लंबे होने से पर्व निकल गया और वल्टे से लौट गया एक वाक्या भरे साथ भी हुई स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर लोकमान्य तिलक को 9नवंबर का था जो पटना से मुंबई हेतु था करीब 41घंटे का विचल्य हुआ जिसे लिखा गया चार्ट बना लेकिन टिकट ऑनलाइन कैसिल ना हो सका एक तो

ईवीएम पर संदेह की उंगली

हरियाणा विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित परिणामों ने पूरे देश के न केवल सभी प्रमुख एजेंसीज द्वारा किए गए एक्विट पोलस को बुरी तरह झुटला दिया था, बल्कि बड़े-बड़े राजनैतिक विश्लेषकों को भी हैरानी में डाल दिया था। मसलन, अनेकों सांसदों ने ही बताया कि किस तरह बिना कोरम पूरे किए ही महत्त्वपूर्ण पन एजक्विट डायनोसिस' छपी। जिसमें खुद सांसदों ने यह स्वीकारा था कि प्रश्न तर्ह का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार सदन में करते हैं। मसलन, सांसदों ने ही बताया कि किस तरह बिना कोरम पूरे किए ही महत्त्वपूर्ण दस्तखत इसलिए करते हैं कि उन्हें भत्ते के रूप में मिलने वाली धनराशि 1000 मिल जाए। सांसदों ने यह भी बताया कि प्रश्न पूछने के लिए किस तरह के गैर-जिम्मेदाराना कार्य किए जाते हैं, जिनसे अपने क्षेत्र या देश का हित नहीं

ईवीएम पर संदेह की उंगली

विधानसभा के नतीजे कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित थे, इसलिए कांग्रेस ने सौधा आरोप लगा दिया कि हरियाणा चुनाव में उसे हराया गया है। उसका आरोप था कि कई जगह ईवीएम का हैक किया गया। इस सबके बीच सवाल यह भी उठा कि अनेक ईवीएम इंजींकेटर में बैटरी की मात्रा 90 व 95व तक मिनट दिखा रही थी, जबकि मतदान के अंत में ईवीएम में हैं, उस समय राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि एमके स्टालिन और फारूक अब्दुल्ला जैसे अनेक बड़े नेताओं ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया था। और उस समय भी सभी का ईवीएम को लेकर एक ही स्वर था कि यदि उनकी सरकार आणी तो वे ईवीएम को हटा देंगे। सवाल यह है कि हरियाणा के साथ-साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव परिणाम आए तो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस गठबंधन को मिले स्पष्ट बहुमत को स्वीकारा जा रहा है, लेकिन हरियाणा में भाजपा को मिली जीत प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को पच नहीं पा रही। और वे खिसियायी बिल्ली खंबा नोचे के अंदाज में अपनी हार को भड़पस ईवीएम के त्रुटिपूर्ण होने की बात कहकर निकाल रहे हैं। बेशक, लोकतंत्र को सबको अपनी बात या राय रखने का हक है, लेकिन आचरण में दोहरापन नहीं होना चाहिए। यदि कांग्रेस के नेता हरियाणा में ईवीएम की कार्यप्रणाली में त्रुटियाँ निकाल रहे हैं तो फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा परिणामों से सहमत क्यों? इससे पता चलता है कि वे अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और चुनाव प्रक्रिया का अभिन्न अंग अविश्वसनीय अंग बन चुके जरिए पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

कविता प्रेम का तस्वर

**घटती-घटना**  
कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी  
गांधीनगर, इंदौर, मध्यप्रदेश

मैं भोले को जब भी पुकारूँ, भोले मेरे पल में आते, सौथो बनकर साथ निभाते, जीवन का हर सुख दे जाते। मैं भोले को .... कहीं भाव मेरे जग जाते, तभी भोले मुझको मिल जाते, बात-बात में वो मुझको फिर, जीवन का नव गीत सुनाते। मैं भोले को.... सुजन किया भोले ने जीवन, मेरे दिल की हर धड़कन में, भोले ने धांसें ज्योत दी हैं, जैसे दीप जले ज्योत में। मैं भोले को .... करते हैं सब नमः शिवाय, भोले के दिल में बस जाएं, जीवन बने प्रेम का तस्वर, भक्ति रसों से मन भर जाएं। मैं भोले को ...

# अक्षय नवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की आंवला पेड़ की पूजा

- संवाददाता -

अम्बिकापुर, 10 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)।

अक्षय नवमी के अवसर पर रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आंवला पेड़ के नीचे विधि-विधान पूर्वक पूजा-अर्चना की तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिर परिसर व पिकनिक स्थल में आंवला पेड़ के नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ होने से रोक बनी रही। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि नवमी से लेकर पूर्णिमा तक आंवला पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है तथा इस दिन पेड़ के नीचे विधि-विधान से पूजा अर्चना करने पर वतियों की मनोकामना पूर्ण होती है। अक्षय नवमी के अवसर पर सुबह से ही मंदिर परिसर स्थित आंवले पेड़ के नीचे बड़ी संख्या श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने पहुंचे। इसके अलावा संजय पार्क, बांकी डेम व चुनचुड़ डेम में भी काफी संख्या में लोग आंवला पेड़ की विधि-विधान से पूजा कर परिवार की खुशहाली की कामना की। इस दौरान सपरिवार आंवले पेड़ के नीचे प्रसाद ग्रहण किया। अक्षय नवमी पर शहर के सभी पार्कों में भीड़ रही। लोगों ने पूजा करने के बाद वन भोज का आनंद लिया।



# समूह से फर्जी तरीके से लोन निकलवाकर नहीं भर रहा था किशत, आरोपी गिरफ्तार

- संवाददाता -

अम्बिकापुर, 10 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)।

एक व्यक्ति फर्जी तरीके से महिला स्वयं सहायता समूह से 6 लाख 43 हजार रुपये लोन निकलवा लिया था। इसके बाद लोन का करत भी नहीं पटा रहा था। परेशान महिलाओं ने मामले की रिपोर्ट लुण्डा थाना में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिसने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिसने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।



अन्यपूर्ण फार्मिनेस प्राइवेट लिमिटेड स्वयं सहायता समूह के सदस्य आरती एवं अन्य महिलाओं को लोन की राशि पर ब्याज देने का झांसा देकर दरिमा निवासी संतोष उर्फ राजू सोनी ने 6 लाख 43 हजार रुपये का लोन निकलवाया था। कुछ दिनों तक लोन का किशत वह पटाया

इसके बाद किशत पटना बंद कर दिया था। समूह की महिलाओं ने मामले की रिपोर्ट लुण्डा थाना में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिसने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर रही थी। विवेचना के क्रम में पुलिसने आरोपी संतोष उर्फ राजू सोनी उम्र 45 साल निवासी दरिमा को गिरफ्तार किया है। पुलिसने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी लुण्डा उप निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, उप निरीक्षक नवल दुबे, प्रधान आरक्षक नामूल राम, आरक्षक दीपक पाण्डेय शामिल रहे।

# तलवार दिखाकर डरा-धमका रहा युवक गिरफ्तार

- संवाददाता -

अम्बिकापुर, 10 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)।

कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। हाथ में तलवार लेकर युवक लोगों को डरा धमका रहा था।



जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के बौरीपारा स्थित महादेव गली रोड में 9 नवंबर को एक व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिसने आरोपी के कब्जे से तलवार भी जब्त किया है। पुलिसने आरोपी सूरज साव उम्र 24 वर्ष निवासी खेरवार के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।



# सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 7 पर वैधानिक कार्रवाई

- संवाददाता -

अम्बिकापुर, 10 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)।

सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब सेवन करने के मामले में सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को अभियान चलाकर कोतवाली व मर्णपुर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है।

थाना कोतवाली क्षेत्र के गड्ढाघाट खेरवार रोड में कुछ लोग अलग-अलग स्थान पर बैठकर सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन कर रहे थे। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी युवा श गुना, सेंटि गुना निवासी अम्बिकापुर, अरुण गुना

निवासी गायबुड़ा थाना बगीचा, आकाश यादव निवासी पटोरा लुण्डा, शंकर यादव निवासी घुघरी बगीचा जशपुर व मनोहर बेहरा निवासी लरंगा थाना सन्ना जिला जशपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिसने इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। वहीं थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा कन्या महाविद्यालय मैदान परिसर के पास से सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पाए जाने पर आदर्श गुना उम्र निवासी गांधीनगर को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की है। वहीं चौकी केरजू द्वारा अवैध महुआ शराब बिक्री के मामले में कार्रवाई करते हुए धनेश्वर चौहान उम्र 52 वर्ष निवासी कुनमेरा चौकी केरजू के कब्जे से कुल 4 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया है। पुलिसने आरोपी के विरुद्ध 34(1)क, ख आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

# 11 हाथियों के दल ने पण्डो जनजाति के दो बच्चों को पटक कर मार डाला

एक 7 वर्षीय भाई ने हाथियों के सामने ही छुप कर बचाई जान, प्रत्यक्ष रूप से देखा भाई-बहन को मारते



- संवाददाता -  
प्रेमनगर, 10 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)।

घने जंगल में मवेशी चराकर जीवन पोजन करने गए ग्रामीणों के घर मातम पसर गया है। बीते रात में पण्डो ग्रामीण अपने फूस की झोपड़ी में सो रहे थे कि तभी आधी रात्रि में 11 हाथियों का दल अचानक ही झोपड़ी में आ गया और एक दंपति अपने दो बच्चे को लेकर भागने में सफल हो गया किंतु अपने एक बेटा, और बेटों को बचा नहीं पाया, हाथियों ने कुचल कर भाई-बहन की जान ले

ली है। मौके पर वन अमला की टीम, भाजपा नेताओं ने दुःख जाहिर करते हुए परिवार को 50 हजार रुपये का सहायता प्रदान किया है।

जानकारी के अनुसार रामानुजगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम महेशपुर टनटलिया पहाड़ जिसे मुलकी पहाड़ भी कहा जाता है, वहां प्रेमनगर बरईडांड निवासी पंडो परिवार के दो दंपति पिता पुत्र अपने बहु नाती के साथ झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं। और मवेशी चराने का काम किया करते हैं। हमेशा की तरह भिखू राम अपने बच्चे पत्नी के साथ ही सोया हुआ था। कि तभी बीते रात्रि को करीब 1 बजे 11 हाथियों का दल झोपड़ी में अचानक ही आ धमके भिखू राम अपने पत्नी और 5 बच्चे के साथ में सोया हुआ था। तभी हाथी के धमक से घबरा कर भिखू राम अपने पत्नी के साथ दो बच्चे को उठाकर भाग गया, और झोपड़ी 3 बच्चे बचे हुए थे। जिन्हें भी निकालने की कोशिश करने लगा था कि तभी एक हाथी उसके पीछे दौड़ने लगा, भिखू राम पण्डो अपनी जान बचाते हुए दूसरे झोपड़ी में पिता के पास जाकर भागने को कहने लगा

सभी दूर गड्डे में भाग कर जान बचा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर झोपड़ी में मौजूद भिखू राम पण्डो के तीन बच्चे झोपड़ी में फंसे हुए थे। एक बच्चा देव सिंह उम्र 8 वर्ष, हाथियों की आट्ट सुन कर झोपड़ी से बाहर निकल कर एक किनारे में छुप गया वहीं झोपड़ी में सोए 11 वर्षीय बेटा टिशु व 5 वर्षीय काजल को हाथियों के दल ने झोपड़ी से बाहर निकाल कर कुचलकर मार डाला, इस घटना क्रम को 8 वर्षीय देव सिंह देख रहा था। घटना की सूचना पर वन अमला घटना स्थल

पहुंचकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली है और ग्रामीणों को हाथियों से बचने की सलाह दी है। बताया जाता है कि पिछले 3 नवंबर से हाथियों का यह दल रामानुजगर वन परिक्षेत्र के इन जंगलों में विचरण कर रहा है। वन विभाग लगातार सर्चिंग भी करा रहा है। लोगों को माइक से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। मुलकी पहाड़ की घटना से आसपास के क्षेत्र में जहां शोक का माहौल है। लोग हाथियों के आतंक से भयभीत हैं। इस पहाड़ पर चार- पांच लोग

झोपड़ी बनाकर चरवाहे का काम करते हैं और रात को वहीं रुक जाते हैं। इन सभी लोगों को समझाव देकर वापस घर भेज दिया गया है। बताते हैं कि इस पहाड़ पर जाने के लिए डेढ़ किलोमीटर तक कोई रास्ता नहीं है। पैदल ही जाया जा सकता है। वन विभाग के रेंजर रामचंद्र प्रजापति ने भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र जायसवाल, मंडल अध्यक्ष जगमोहन सिंह, नोहर साहू के माध्यम से मृतक के परिवार को 25-25 हजार रुपये नगद तात्कालिक सहायता राशि दी है।

# बीयर लेकर नशे में धुत्त नाच रहे ये सरकारी कर्मचारी, जमकर वायरल हो रहा वीडियो, SDM ने लिया संज्ञान

» वहीं नशे में धुत्त कर्मचारियों का हाथ में बीयर का बॉटल लेकर डांस करते हुए का वीडियो वायरल होने के बाद सरगुजा जिला प्रशासन ने वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लिया है।



वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लिया है। वहीं इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत में सीतापुर SDM रवि राही ने बताया कि वायरल वीडियो शासकीय हाउसिंग बोर्ड कालोनी मैनापट के बाहर का नजर आ रहा है जिसमें जनपद के कुछ कर्मचारी अपने हाथ में बीयर

का बॉटल लेकर नशे में धुत्त होकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वहीं सीतापुर SDM रवि राही ने यह भी बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर संबंधितों के खिलाफ नोटिस जारी कर वायरल वीडियो के संदर्भ में जवाब मांगा जाएगा और आगे उचित कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि नशे में धुत्त होकर ऐसा कृत्य करना जनपद के कर्मचारियों को शोभा नहीं देता है और यह अनुचित है।

**आवश्यकता है**

**दैनिक अखबार घटती घटना**

**में मशीन हेलफर की आवश्यकता है**

कार्य समय: शाम 7 बजे से देर रात तक

**इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें**

**संपर्क-संत हरकेवल विद्यापीठ के पास, नमनाकला**

**अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़, मो. 9826532611**

योग्यता 10वीं पास

वेतन 7 से 10 हजार

# लेबनान में हिजबुल्लाह से युद्धविराम और निशाने पर गाजा, इजरायल के मन में क्या छिपा

इजरायल, 10 नवम्बर 2024। इजरायल इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह दोनों के खिलाफ खतरनाक जंग लड़ रहा है और मौजूदा परिस्थितियों को देखते तो इस युद्ध का अंत दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा। सभी एक-दूसरे का अंत चाहते हैं और तब तक रुकने नहीं वाले। इस बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि इजरायल कथित तौर पर उत्तरी सीमा में लेबनान के साथ चल रहे सैन्य अभियान को कुछ वक्त के लिए रोकना चाहता। इजरायली समाचार चैनल 12 की रिपोर्ट है कि इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ कुछ देर के लिए युद्धविराम चाहता है। इसके पीछे की चौकाने वाली वजह भी सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल का ऐसा करने के पीछे की वजह गाजा में हमास के खिलाफ चल रहा युद्ध है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध को एक साल से अधिक



हो चुका है और भीषण नरसंहार के बाद इजरायल से पूरी दुनिया खफा है। जेरूसलम पोस्ट ने एन12 न्यूज के हवाले से बताया कि इजरायल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के फैसले को टालने के लिए ऐसा करना चाहता है। मामला यू है कि यूएनएससी गाजा

समझौते का विवरण अभी अज्ञात है, लेकिन इजरायल को लगता है कि यूएनएससी संभवतः गाजा में इजरायल को लड़ाई रोकने या इजरायल पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करेगी। इजरायल का कहना है कि उसने हमास के आतंकवादियों से लड़ने के लिए जो वहां से हमला किए थे, उन्हें फिर से संगठित होने से रोकने के लिए एन्क्लेव के उत्तर में जबालिया, बेत लाहिया और बेत हज़ून में सेना भेजी थी। उसका कहना है कि नए हमले की शुरुआत के बाद से उसके सैनिकों ने उन इलाकों में सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब रविवार को सुबह उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया में एक घर पर इजरायली हमले में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। फिलिस्तीनी सरकारी समाचार एजेंसी झुन्न और हमास मीडिया ने मरने वालों की संख्या 32 बताई है, मरने वालों में

**लेबनान में अटक से कई बच्चों समेत 40 की मौत**  
लेबनान पर पिछले दिन के इजरायली हवाई हमलों में कई बच्चों सहित कम से कम 40 लोग मारे गए। लेबनानी अधिकारियों ने कहा, इजरायली बमबारी से रात भर राजधानी बेरुत के दक्षिणी उपनगरों पर आग के गोले बरसते रहे। लेबनान ने बताया कि मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। बचाव अभियान जारी है और हमले के बाद बरामद किए गए अन्य शवों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण किया जाएगा। अधिकतर बच्चे और महिलाएँ हैं।

# भारत से बढ़ते तनाव के बीच कनाडा के दो अहम फैसले, भारतीयों पर कितना असर ?



**ओट्टावा, 10 नवम्बर 2024।** भारत से तनाव के बीच कनाडा ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसका असर वहां पढ़ने के इच्छुक भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। कनाडा ने फास्ट ट्रैक स्टडी वीजा प्रोग्राम, एसडीएस को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) बहुत पॉपुलर थी और इसके तहत अल्पाई करने से लेकर अप्रुवत तक में काफी कम समय लगता था। बता दें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस बारे में

सितंबर में ही बोल दिया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि हम इस साल 35 फीसदी कम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को परमिट देंगे। अगले साल से इसमें दस परसेंट की और कमी आएगी। इसके अलावा कनाडा अपने पूर्व के इमिग्रेशन से जुड़े कदम से भी पीछे हट रहा, जो कम कुशल श्रमिकों के लिए थी। इसके तहत भी भारत से बढ़ी संख्या में श्रमिक आते थे। कनाडाई प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि अप्रवासी

हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फायदा पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब कुछ बुरे लोग सिस्टम को कोसते हैं और छात्रों का फायदा उठाने लगते हैं तो ऐकशन लेना पड़ता है। कनाडाई सरकार ने कहा कि वह अस्थायी छात्रों की संख्या कम करना चाहती है। यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद चरम पर है। कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के मुताबिक यहां पर सबसे ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। इनकी अनुमानित संख्या 4,27,000 है। आब्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी) ने शुक्रवार को इस बारे में एक बयान जारी किया। इसमें उसने कहा कि कनाडा सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को स्टडी परमिट के लिए अप्लीकेशन प्रॉसेस में समान और उचित पहुंच देने के लिए प्रतिबद्ध है। एसडीएस प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया था। इसके जरिए कनाडा में उच्च शिक्षा लेने के इच्छुक छात्रों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया गया।

# निज्जर से ज्यादा हत्याएं, गोल्डी बरार का पार्टनर; कौन है कनाडा में पकड़ा गया खालिस्तानी अर्श डाला



**कनाडा, 10 नवम्बर 2024।** कनाडा की पुलिस ने खालिस्तानी अर्श डाला उर्फ अर्शदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। अर्श डाला कौन है? इसे लेकर चौकाने वाली जानकारी सामने आई है। कनाडा में चरमपंथी गतिविधियों में वह शामिल है। डाला खालिस्तानी हरदीप सिंह का चेला जखर था, लेकिन उसके नाम निज्जर से ज्यादा हत्या के रिकॉर्ड हैं। यह कुख्यात आतंकी गोल्डी बरार का पार्टनर भी है। पंजाब में कई हाई प्रोफाइल किलिंग में शामिल है।

**अर्श डाला कौन है ?**  
पंजाब के मोगा जिले के दल्ला गांव का रहने वाला 27 वर्षीय अर्शदीप सिंह खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) जैसे चरमपंथी समूहों से जुड़ा हुआ है। वह कई संगठित आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और कुख्यात कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बरार से भी जुड़ा हुआ है। अर्शदीप अपनी पत्नी और एक नाबालिग बेटी के साथ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में रह रहा है। उसके पास 1 सितंबर, 2017 को जालंधर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट है, जो 31 अगस्त 2027 तक वैध है।

# बलूचिस्तान कैसे बन गया दर्द देने वाला नासूर, जिससे अब बिलबिला रहा पाकिस्तान



**नई दिल्ली, 10 नवम्बर 2024।** पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में हाल के दिनों में एक बार फिर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। शुक्रवार को एक पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में स्कूली बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गयी थी। वहीं शनिवार को क्रेटा में हुए धमाके में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी। ये बम धमाका क्रेटा रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। बलूच नेता लंबे समय से बलूचिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार पर इस हिस्से की तरफ से उपेक्षा और शोषण का आरोप लगाता रहा है। बलूचिस्तान एक विशाल

**काफी पुरानी है अलग बलूचिस्तान की मांग**  
9वीं सदी में अंग्रेजों ने बलूचिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। अंग्रेजों ने बलूच क्षेत्रों को विभिन्न राज्यों में विभाजित कर शासन की शुरुआत की थी। 1947 में भारत के विभाजन के समय, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से पाकिस्तान में शामिल हो गए। बलूच नेताओं ने पाकिस्तान में विलय का विरोध किया था और स्वतंत्र राज्य की मांग की थी। 1948 से ही बलूचिस्तान में सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे सशस्त्र समूह पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने बलूच आंदोलन को दबाने के लिए कई बार सैन्य कार्रवाई की है। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई आरोप लगते रहे हैं।

**बलूच आंदोलन के प्रमुख कारण क्या हैं ?**  
बलूच लोग अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान के खत्म होने की आशंका जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। बलूचिस्तान में खनिज संपदा और प्राकृतिक गैस जैसे समृद्ध संसाधन हैं। हालांकि उस क्षेत्र में बेहद गरीबी है। बलूचिस्तान में विकास की गति धीमी है और बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी देखने को मिलती है। पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूच लोगों पर अत्याचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण

# महरंग बलोच के नेतृत्व में जारी है अहिंसक आंदोलन

31 वर्षीय बलूची महिला महरंग के नेतृत्व में बलूचिस्तान में महिलाओं की तरफ से तीव्र आंदोलन चल रहा है। 2017 में महरंग के भाई का अपहरण कर लिया गया था। महरंग इस घटना के बाद आंदोलन में सक्रिय हुईं। उन्होंने 2019 में बलूच यकजहेती समिति (BYC) की स्थापना की थी। महरंग का कहना है कि मैं मौत से भी अब नहीं डरती हूँ। वो पोशे से डैवट रहती हैं। रूढ़िवादी बलूचिस्तान में महिला सामाजिक कार्यकर्ता महरंग को लोग खूब पसंद कर रहे हैं उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में महिला सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं।

**बलूचिस्तान आंदोलनकारियों की रही है कई तरह की मांग**  
बलूचिस्तान आंदोलनकारियों की मांगें समय के साथ बदलती रही हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग बलूचिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता या पूर्ण स्वतंत्रता है। वे चाहते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए, जहां वे अपनी संस्कृति, भाषा और संसाधनों पर नियंत्रण रख सकें। हालांकि समय-समय पर पाकिस्तानी सरकार के साथ कई बार समझौते भी हुए हैं। बलूच आंदोलनकारी चाहते हैं कि इन संसाधनों से होने वाले लाभ को पाकिस्तान का एक अभिन्न अंग मानता रहा है। वो किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को इस क्षेत्र में रोकना चाहता है। पाकिस्तान को डर है कि भारत और अफगानिस्तान जैसे देश बलूच आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और बलूचिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं।

# नाटो से बाहर आणा ट्रंप का अमेरिका ? क्यों डरा हुआ है हथियार दिखाकर रूस को धमकाने वाला यूरोप

**इस्लामाबाद, 10 नवम्बर 2024।** अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से ही नाटो के भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों को आशंका है कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका नाटो से अलग हो सकता है। यह शंका इसलिए की जा रही है कि क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने नाटो के खिलाफ कई फैसले लिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने नाटो सदस्य देशों को उनके मुंह पर धमकाया भी था। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसे संकेत दिए हैं कि नाटो को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। ऐसे में सदस्य देश डर रहे हैं कि कहीं रूस के खिलाफ उनकी को गई मेहनत पर पानी न फिर जाए।

**ट्रंप कर सकते हैं कानून को बाईपास ?**  
कानूनी विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ट्रंप विदेश नीति पर राष्ट्रपति के अधिकार का हवाला देते हुए कांग्रेस के नाटो सुरक्षा घेरे को दरकिनार करने की कोशिश कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका जिसका इस्तेमाल उन्होंने संधि वापसी पर कांग्रेस के प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए पहले भी किया था। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के विद्वान और लॉफियर के वरिष्ठ



**ट्रंप के खिलाफ कानूनी कदमों पर स्थिति साफ नहीं**  
एंड्रसन ने कहा, यह खुला और बंद नहीं है, यह कांग्रेस द्वारा आपको यह बताने के बारे में है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अगर आप कांग्रेस की अनदेखी करते हैं, तो आपको इस पर अदालतों में हमसे लड़ना होगा। वहीं, शिकागो लॉ स्कूल विश्वविद्यालय में एलन एम. सिंगर प्रतिष्ठित सेवा प्रोफेसर कर्टिस ब्रेडली के अनुसार, अगर ट्रंप ने केवल यह घोषणा की कि वह गठबंधन से बाहर निकल रहे हैं, तो यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस के पास कानूनी की अनदेखी करने के लिए उन पर मुकदमा चलाने का कानूनी अधिकार होगा या नहीं।

**अमेरिका में संवैधानिक प्रश्न अस्पष्ट**  
एंड्रसन ने कहा कि सांसदों को मुकदमेबाजी को स्पष्ट रूप से अधिकृत करने वाली भाषा जोड़कर कानून को मजबूत करना चाहिए, जिससे कांग्रेस के न्यायालय में खड़े होने की संभावना बेहतर होगी। उन्होंने यह भी बताया कि जबकि कांग्रेस के पास नाटो से राष्ट्रपति के हटने पर मुकदमा करने के लिए सबसे मजबूत आधार है, सेवा सदस्य या निजी व्यक्ति-जैसे कि अमेरिकी जो नाटो देशों में संपत्ति रखते हैं - के पास संभावित तर्क हो सकते हैं, लेकिन

**कांग्रेस ने कभी नहीं दी है सीधी चुनौती**  
कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रपति द्वारा संधि से हटने को सीधे कानूनी चुनौती नहीं दी है। एंड्रसन ने कहा, यह बहुत ही विवादित कानूनी क्षेत्र है, और यह 100 प्रतिशत स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ट्रंप ऐसा करने में सक्षम होते हैं, तो वापसी जल्दी ही हो जाएगी। नाटो संधि के तहत, एक सदस्य देश को निर्णय के बारे में अन्य सदस्यों को सूचित करने के लिए निंदा का नोटिस प्रस्तुत करना होगा। एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि के बाद ही देश को सदस्यता आधिकारिक रूप से समाप्त होगी।

# तेज होने वाला है युद्ध ! रूस की राजधानी पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन हमला...कई पलाइंटें डायवर्ट



**कोव, 10 नवम्बर 2024।** यूक्रेन ने रविवार को मांसको पर 34 ड्रोन के साथ हमला बोला। यह युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी राजधानी पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। हमले की वजह से शहर के तीन प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा और एक व्यक्ति घायल हो गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी रूस के अन्य क्षेत्रों में 36 अन्य ड्रोन को नष्ट किया गया। रूस की संघीय हवाई परिवहन एजेंसी ने कहा कि ड्रोमोडेडोवो, शेरेंमैतयेवो और जुकोवस्की के हवाई अड्डों ने 36 उड़ानों को डायवर्ट किया। हालांकि, बाद में परिचालन सामान्य हो गया। वहीं, रूस ने भी यूक्रेन पर हमला बोला है। रूस की ओर से रातभर के दौरान 145 ड्रोन यूक्रेनी क्षेत्र में भेजे गए। कोव ने कहा कि उनमें से 62 को मार गिराया गया। यूक्रेन ने यह भी कहा कि उसने

# एसएसपी सूरजपुर ने छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश की सीमा से लगे अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट नवाटोला का किया औचक निरीक्षण

थाना चांदनी व चौकी मोहरसोप का किया आकस्मिक निरीक्षण, चेकपोस्ट पर हर आने-जाने वाले पर पैनी निगाह रखने की हिदायत दी

-संवाददाता-  
सूरजपुर, 10 नवम्बर 2024  
(घटती-घटना)।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के बार्डर पर स्थित नवाटोला चेकपोस्ट का निरीक्षण किया यहां 24 घंटे पुलिस व प्रशासन के अधिकारी व जवानों का कड़ा पहरा लगा हुआ है। उन्होंने चेकपोस्ट पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरा का जायजा लिया, तैनात अधिकारी व जवानों को पूर्ण सजगता के साथ अवैध गांजा व शराब सहित अवैध गतिविधियों-कार्यों के विरुद्ध सख्ती से कार्य करने एवं आने-जाने वाले सदिग्ध वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए।

एसएसपी ने थाना चांदनी व चौकी मोहरसोप का औचक निरीक्षण कर प्रभारी व विवेचकों को कक्षा में मिलाया, बच्चों, वृद्धजन एवं समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनकी शिकायतों पर तत्काल विधि संगत कार्रवाई करते हुए उन्हें राहत दिलाए, शिकायत लेकर आने



वाले ग्रामीणों के समस्या को बड़े आत्मीयता से सुने और त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। थाना चौकी के औचक निरीक्षण के दौरान जवानों के समस्याओं को जाना और निराकरण का आश्वासन दिया। दुरस्थ स्थित चांदनी थाना में जवानों के रहने की सुविधा की जानकारी ली

और आवास निर्माण का प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए। चेकपोस्ट पर हर आने-जाने वाले पर पैनी निगाह रखने की हिदायत दी। जिले के दुरस्थ स्थित थाना-चौकी के कार्यों को जानने, पुलिस की सक्रियता को परखने, अंतर्राज्यीय सीमा पर बने चेक पोस्ट पर जवानों की सक्रियता का



जायजा लेने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने शनिवार को सर्वप्रथम थाना चांदनी अन्तर्गत मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित नवाटोला चेकपोस्ट का जायजा लिया। चेकपोस्ट पर कड़ी चौकसी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन कर फुटेज

रिकार्डिंग क्षमता को जाना और बेहतर रख-रखाव के निर्देश दिए। तैनात अधिकारी व जवानों को कक्षा में मिलाया, बच्चों, वृद्धजन एवं समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनकी शिकायतों पर तत्काल विधि संगत कार्रवाई करते हुए उन्हें राहत दिलाए, शिकायत लेकर आने

में धान का अवैध परिवहन न होने पाए। इस दौरान थाना-चौकी मौजूद रहे। थाना-चौकी का किया निरीक्षण, ग्रामीणों से हुए रूबरू। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना चांदनी का औचक निरीक्षण किया इस दौरान थाना के रिकार्ड को देखा। थाना प्रभारी को ललित मामलों का विधि सम्मत समय पर निराकरण करने, सामुदायिक पुलिसिंग के आयोजन प्रत्येक ग्रामों में किए जाने एवं बीट क्षेत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी व जवानों को सजगता के साथ पेट्रोलिंग व रात्रि गश्त करने के निर्देश दिए। रोजानामचा और रिकार्ड संधारण की स्थिति बेहतर देख संतोष व्यक्त करते हुए और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में पुलिस के कार्यों को जानने के ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनसे संवाद कर पुलिस के कार्यों को जाना और पुलिस के कार्यों में सहयोग करने की अपील किया। उन्होंने चौकी मोहरसोप का भी आकस्मिक निरीक्षण कर पुलिस के कार्यों को जाना।

## रक्षक ही बने भक्षक: तमोर पिंगला अभ्यारण्य में वन्यजीवों का हो रहा अवैध शिकार

विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से वन्यजीव संरक्षण योजनाओं पर संकट



वन्यप्राणियों का शिकार... संरक्षण के बजाय विनाश

सूत्रों के अनुसार, तमोर पिंगला अभ्यारण्य में शाकाहारी वन्यप्राणी, जैसे चीतल, नीलगाय, और कोटरी प्रजाति के जानवरों को संतुलित खाद्य श्रृंखला के उद्देश्य से सन 2022-23 में घास के मैदान में छोड़ा गया था। इन सभी जानवरों का पहले मेडिकल परीक्षण किया गया और उसके बाद उनके प्रजनन एवं भोजन की सुविधाएं मुहैया कराई गईं। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि इन वन्यजीवों का अवैध शिकार लगातार होता रहा।

मेहमानों के निवाले बने वन्यजीव, मांस और छाल की तस्करी

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, कई वन्यजीवों को जंगल में घूमने वाले शिकारियों ने निशाना बनाया, वहीं कुछ जानवर अभ्यारण्य में आने वाले विशिष्ट मेहमानों का निवाला बन गए। अवैध शिकार के बाद इन जानवरों की खाल को लाखों रुपये में खरीदा गया और तस्करी द्वारा ऊँचे दामों पर बाहरी बाजारों में बेचा गया। ये घटनाएं विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करती हैं, जिन्होंने इस अवैध कार्य को रोकने के बजाय बढ़ावा दिया।

विभागीय मिलीभगत से योजनाएं कागजों में सिमटी

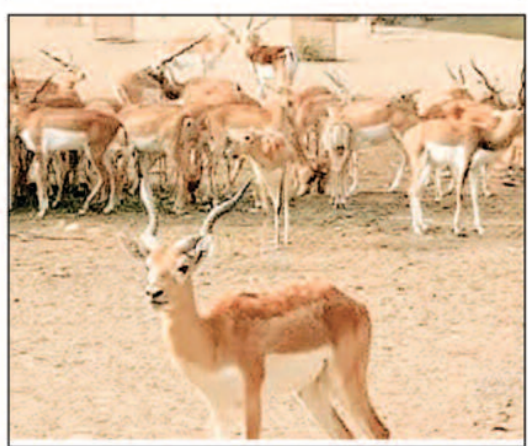
केंद्र सरकार द्वारा वन्यप्राणियों के संरक्षण और प्रजनन को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। परंतु इस अभ्यारण्य में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन, वन्यजीवों का संरक्षण और संवर्धन कार्यक्रम भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते विफलता की कगार पर है।

जांच की मांग, लेकिन दोषी अधिकारी अब भी बचे हुए

विगत घटनाओं के बावजूद, विभागीय अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच न होने के कारण दोषी कर्मचारी लगातार बचते आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव प्रजनन और संरक्षण योजनाओं के लिए आवंटित भारी भ्रूषण बजट का दुरुपयोग हो रहा है। विभागीय अधिकारियों की अनदेखी और शिथिलता के कारण संरक्षण की सारी योजनाएं विफल होती दिख रही हैं।

-सोनु कश्यप-  
प्रतापपुर, 10 नवम्बर 2024  
(घटती-घटना)।

प्रतापपुर विकासखंड के रमकोला तमोर पिंगला अभ्यारण्य,जिसे वन्यजीव संरक्षण और प्रजनन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, भ्रष्टाचार और विभागीय लापरवाही का शिकार बनता जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा यहां वन्यप्राणियों की देखरेख और उनके प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपये की योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता और मिलीभगत के कारण ये योजनाएं मात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई हैं।



## जनता में रोष और वन्यजीव संरक्षण पर गंभीर संकट

वन्यजीव संरक्षण में हो रही इस घोर लापरवाही को लेकर जनता में आक्रोश है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर वन्यप्राणियों की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी का पालन न होना न केवल कानून व्यवस्था का मजाक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की गंभीरता पर भी प्रश्न खड़ा करता है। वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग अब जोर पकड़ रही है। इस विषय में तमोर पिंगला वन अभ्यारण्य डीएफओ टी श्रीनिवास ने बताया कि संबंधित वन प्राणियों का संरक्षण होना था इस विषय में जांच करके समस्त बिंदुओं पर कार्यवाही करते हुए जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तथा उक्त जानवरों की जंगल में मुनादी कराई जाएगी हलांकि जंगल में वन प्राणी कम नजर आ रहे हैं। जिस पर कड़ी जांच कार्रवाई करते हुए शासन को अवगत कराकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, तथा गेम रेंजों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

## सरपंच-सचिव विकास की राशि का कर रहा बंदरबांट

ग्राम पंचायतों में चल रहा जीएसटी का खेल... क्या निर्माण कार्य का ले-आउट भौतिक सत्यापन नहीं करते इंजीनियर?

-राजेंद्र शर्मा-  
खड़गवां, 10 नवम्बर 2024  
(घटती-घटना)।

सरकार द्वारा गांव को मुख्य धरा से जोड़ने के लिए पानी की तरह राशि स्वीकृत कर रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गंगा बह सके। खड़गवां विकास खण्ड में ऐसा हो गया है कि सरकार द्वारा जो राशि जारी किया जाता है उस राशि का बंदरबांट करने का जिम्मा जनपद पंचायत अधिकारी द्वारा सरपंच-सचिव को दे दिया है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्राम पंचायत में कार्य हुआ कि नहीं इसके ज्ञानके तक ना ही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ना ही ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के उपमंत्री अनुविभागीय अधिकारी जाते नहीं हैं। जिसके कारण बिना काम कराए ही निर्माण कार्य की राशि सरपंच-सचिव द्वारा निकाल लिया जाता है। निर्माण कार्य की राशि आहरण करने से पहले निर्माण कार्य का लेआउट मूल्यांकन भौतिक सत्यापन इंजीनियर द्वारा किया जाता है उसके बाद ही राशि आहरण करने की अनुमति मिलती है। लेकिन



खड़गवां जनपद पंचायत में शासन के इस नियम की खुलकर धजियां उड़ाई जा रही है सिर्फ कमिशन के नाम पर जनपद पंचायत और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में चल रहा है? ऐसा लगता है कि यहां किसी प्रकार की कोई लेआउट मूल्यांकन सत्यापन करने की जरूरत नहीं

पड़ती है। ऐसा ही राशि आहरण काम कराए ही लाखों-लाखों का कर ली जाती है। तभी तो बिना बिल भुगतान हो जा रहा है।

इस संबंध में ग्राम पंचायत कौडीमार के सचिव से सी सी सड़क निर्माण कि राशि आहरण करने के संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने ने कहा कि राशि तो 2022-23 में ही आहरण कर ली गई है सी सी सड़क का निर्माण कार्य आज तक नहीं कराया गया है।

परमेश्वर सिंह, ग्राम पंचायत कौडीमार सचिव

## सरपंच-सचिव ग्राम पंचायत में खेल रहे फर्जी बिल लगाकर जीएसटी-जीएसटी

खड़गवां जनपद पंचायत में ऐसे कई सरपंच सचिव हैं जो अपने रिश्तेदारों के नाम पर जीएसटी नंबर जारी कराए हैं जो सिर्फ ग्राम पंचायत में फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए का आहरण कर रहे हैं। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई फर्म या दुकान नहीं है जिससे वह समान सप्लाई कर सकें। हां लेकिन इनके द्वारा लाखों रुपए का ग्राम पंचायत में बिल दिया जाता है और इनके बिल से सरपंच-सचिव फर्जी तरीके से बिना निर्माण कराए ही शासकीय राशि का बंदर बांट कर करते हैं। ऐसा ही हुआ है कौडीमार ग्राम पंचायत में सी सी सड़क निर्माण में।

## कलेक्टर ने भू-अर्जन के प्रकरणों में निर्धारित अवधि में अवाई पारित करने के लिए किया निर्देशित

-संवाददाता-  
कोरबा, 10 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)।

कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टरों सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर ललित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी राजस्व अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कार्य करें। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई हेतु निर्धारित दिन एवं समय पर उपस्थित रहकर सुनवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ व अपर कलेक्टर श्री दिनेश नाग, संयुक्त कलेक्टर मनोज बंजारे, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर श्री वसंत ने सभी एसडीएम को भू-अर्जन के प्रकरणों में निर्धारित अवधि में अवाई पारित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अविवादित/विवादित नामांतरण, सीमांकन, बटाकन, भू-व्यवस्थापन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का तहसीलदार समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु सभी तहसीलदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय-सीमा से बाहर न हो सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने ज़ुट्टि सुधार के प्रकरणों एवं नक्शा बटाकन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम को मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया।

### नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पुराना नाम नारायण बड़ा, पिता श्री रामेश्वर बड़ा अपना पुराना नाम को बदलकर नया नाम नारायण भगत, पिता-श्री रामेश्वर, निवासी ग्राम-अलौरी तह-मनोरा जिला-जशपुर (छ0ग0) रख लिया हूं। अतः अब मुझे भविष्य में समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय व अन्य दस्तावेजों में नया नाम नारायण भगत पिता-श्री रामेश्वर से जाना एवं पहचाना जाए।

शपथकर्ता  
नारायण भगत,  
ग्राम-अलौरी  
तह-मनोरा, जिला-जशपुर (छ0ग0)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे				
रैलपे ई-नीतामी कार्यक्रम				
माह दिसम्बर - 2024 से फरवरी - 2025 तक का ऑनलाइन रैलपे नीतामी कार्यक्रम विनियमनार है:				
[A] Dec. - 2024				
GSD/Raipur	BSP/Division	Raipur/Division	Nagpur/Division	GSD/NGP
09.12.2024	06.12.2024	05.12.2024	04.12.2024	11.12.2024
20.12.2024	16.12.2024	13.12.2024	12.12.2024	---
31.12.2024	30.12.2024	27.12.2024	24.12.2024	23.12.2024
[B] Jan. - 2025				
GSD/Raipur	BSP/Division	Raipur/Division	Nagpur/Division	GSD/NGP
10.01.2025	09.01.2025	08.01.2025	13.01.2025	07.01.2025
21.01.2025	17.01.2025	16.01.2025	20.01.2025	---
31.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	28.01.2025	24.01.2025
[C] Feb. - 2025				
GSD/Raipur	BSP/Division	Raipur/Division	Nagpur/Division	GSD/NGP
10.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	05.02.2025	13.02.2025
20.02.2025	17.02.2025	18.02.2025	14.02.2025	---
28.02.2025	25.02.2025	27.02.2025	24.02.2025	21.02.2025

कृपया ई-नीतामी के लिए वेबसाइट [www.ireps.gov.in/e-Auction](http://www.ireps.gov.in/e-Auction) पर लॉगिन करें।  
 \* नीतामी 10:00 बजे शुक्र आरम्भ होगी तथा यदि बन्धुत हुआ तो आगे दिन भी जारी रह सकती है। \* सामग्री का निष्पत्त "जहां है वहां" के आधार पर होगा। \* जीएसटी / रायपुर व डिजिटल (बिलासपुर, रायपुर, नागपुर) में उपलब्ध। \* सामग्री का प्रकार रैलपे, रेल, कार्ट आयरन, पी. डे रैलपे, मेटलिंग, एम.एस. कन्वर्ज रोलिंग स्टॉक, नॉन फेरस जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, बेटीरल एवं अहुड्रेनड स्टैंडबर्क आदि। विस्तृत नीतामी कैटलॉग के लिए कृपया वेबसाइट [www.ireps.gov.in/e-Auction](http://www.ireps.gov.in/e-Auction) पर लॉगिन करें।  
 सहायक सामग्री प्रबंधक-II  
 सीबीआर/10/AM/325  
 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर

# क्या कटकोना ग्राम पंचायत पर किसी विशेष एक व्यक्ति का हो गया है कब्जा...हर निर्माण में उनकी दखलअंदाजी?

पंचायत में होने वाले निर्माण ग्रामीण लोगों व पंचायत प्रतिनिधियों की मर्जी से नहीं एक व्यक्ति विशेष की मर्जी से हो रहे हैं:सूत्र

पूर्व सरपंच भी थे खास,वर्तमान भी हैं खास...आने वाले किस सरपंच के साथ होंगे विशेष व्यक्ति?

विशेष व्यक्ति के हस्तक्षेप से पंचायत का हो रहा बंधाधार...चुनाव से पहले पंचायत फंड का वारा न्यारा करने की जुगत में विशेष व्यक्ति

5 साल में पंचायत ने कई लाखों का काम कर दिया पर एक वाटर एटीएम को सुचारू रूप से नहीं चला पाए

वाटर एटीएम सुधार के लिए पंचायत के पास पैसा नहीं पर भ्रष्टाचार वाले निर्माण के लिए पैसे ही पैसे हैं?

कटकोना का वाटर एटीएम पिछले 2 साल से उपयोग विहीन पर पंचायत के पास नहीं है पैसा...एसईसीएल के पैसे से सुधरेगा वाटर एटीएम

वाटर एटीएम सुधारने के लिए भी चहते ठेकेदार को मिला जिम्मा,एक ही संगठन के दो श्रमिक नेता ठेकेदारी में त्यस्त



-रवि सिंह- बैकुण्ठपुर/कटकोना, 10 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत कटकोना में सरपंच कोई भी हो पर एक व्यक्ति विशेष का हस्तक्षेप जरूर देखा जाता है पंचायत के कार्यों में खासकर निर्माण कार्यों

में पूर्व सरपंच के कार्यकाल में भी उनका हस्तक्षेप था, उसके हारने का कारण भी दो गुटों की आपसी असहमति साथ ही तालमेल का अभाव बना, धीरे-धीरे समय बिता और फिर पूर्व सरपंच के हार का गम भूलने के बाद वर्तमान सरपंच के साथ सामंजस्य बैठकर हस्तक्षेप का दौर शुरू हुआ,

कटकोना पंचायत के सरपंच को हटने हटाने का भी दौर चला, अविश्वास प्रस्ताव तक पारित हुआ पर सरपंच के बचने के लिए जिसके पीछे कई कारण हैं और राजनीतिक धुरंधरों की अपनी कहानी है पर अब जब फिर से पंचायत चुनाव सामने खड़ा है तो व्यक्ति विशेष पंचायत मद में पड़े

पैसे को निर्माण कार्य में हस्तक्षेप कर आनन फानन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने पर लगा हुआ है। पंचायत में जो इस समय निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें व्यक्ति विशेष का हस्तक्षेप साफ देखा जा रहा है जो दूसरे गुट को बिल्कुल भी नागवार गुजर रहा है। अब आने वाला समय फिर किस सरपंच

का होगा यह तो समय बताएगा, पर एक बात तो साफ है कि इस बार भी पंचायत में सरपंच बनने को लेकर जो गुट पहले अलग-अलग थे अब वह एक होकर पूर्व सरपंच पर अपना मत एक कर पाएंगे या फिर वर्तमान को ही मौका देंगे क्योंकि संबंध मधुर हो गए हैं।

सूत्रों और ग्राम के लोगों का कहना है कि ग्राम कटकोना में शासकीय राशि की बंदरबाट हो रही है। ग्राम के वाटर एटीएम के लिए अब पंचायत के प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है,वाटर एटीएम खराब है और उसका मरम्मत कैसे हो इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। श्रमिक नेता के साथ कांग्रेस नेता भी पंचायत प्रतिनिधियों को दबाव में लेकर निर्माण कार्य कर जल्द धनाढ्य बनने में लगे हैं वहीं जबकि वाटर एटीएम का लाभ श्रमिक ही प्राप्त करते हैं। बता दें की श्रमिकों को ग्राम में पीने की पानी की दिक्कत लगातार बनी रहती है और कुछ हैंडपंप से दूर से वह पानी लाकर पीने मजबूर रहते हैं। लोगों का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधि और श्रमिक नेता की जुगलबंदी श्रमिक या ग्राम के लोगों के हित में होती तो समझ में आता। दोनों की जुगलबंदी शासकीय राशि खासकर ग्राम के सुविधाओं के राशि के बंदरबाट के लिए हो रही है यह चिंताजनक है। वैसे भी यह गणित राय नाम से प्रसिद्ध है।

## व्यक्ति विशेष का निर्माण कार्यों में हस्तक्षेप गुणवत्ता का ध्यान किसी को नहीं

पंचायत के निर्माण कार्यों में एक व्यक्ति विशेष का हस्तक्षेप छिपा नहीं है। व्यक्ति विशेष ही निर्माण कार्यों के लिए सक्रिय है और एक तरह से एजेंसी है पंचायत के लिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुणवत्ता निर्माण कार्य की सही है, नहीं है, क्या निर्माण कार्य समय अवधि में पूर्ण हुआ नहीं हुआ इसका ध्यान किसी को नहीं है, ध्यान है किसी चीज का तो वह है एक विशेष व्यक्ति को उपकृत करने का। वैसे सरपंच भी मजबूर हैं ऐसा बताया जाता है क्योंकि उसे जितने के लिए श्रमिकों का मत आवश्यक है जिसके ठेकेदार श्रमिक नेता हैं और वह श्रमिकों के मतों का सौदा करके पंचायत में अपना हित साध रहे हैं, निर्माण कार्य करके सम्पन्नता तलाश रहे हैं, वहीं जिन श्रमिकों के हितों की उन्हें जिम्मेदारी श्रमिक नेता होकर निभानी है उनके हितों का ध्यान वह छोड़ चुके हैं क्योंकि वह उन्हीं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बिगाड़ रहे हैं जो श्रमिकों के हित के लिए ही जारी हैं।

## पंचायत चुनाव में भाजपा विधायक का समर्थन का पूर्व सरपंच को जिताने होगा प्रयास

श्रमिक नेता की इसे होशियारी कहें यह चालाकी वह हमेशा अवसर का फायदा उठाने जानते हैं और कब कहां जाकर अपना चेहरा चमकाना है चापलूसी जाहिर करनी है वह इसके लिए तयार रहते हैं। श्रमिक नेता हमेशा नेताओं के इर्दगिर्द रहकर तस्वीर खिंचाने और स्वार्थ अपना साधने में लगे रहते हैं। सरकार कोई हो विधायक कोई हो श्रमिक नेता का जलवा बरकरार रहता है और वह अवसरवादी बनकर सभी से लाभ ले भी लेते हैं झिझक उन्हें नहीं है कोई ऐसा बताया जाता है। बताया जा रहा है वर्तमान विधायक और सरकार में उन्होंने सत्ता बदलते ही तालमेल बैठा लिया है। अब वह पूर्व सरपंच के साथ नजर आ रहे हैं अकेले में जब उन्हें फुसंत मिल रही है निर्माण कार्यों से। पूर्व के साथ मुलाकात इसलिए क्योंकि वह वर्तमान विधायक के खास हैं, वैसे अब श्रमिक नेता का अभियान है कि वह पूर्व सरपंच को पुनः सरपंच बनवाने सहयोगी बने जिससे उन्हें विधायक का साथ मिले। वैसे विधायक भी जानते हैं कि अवसरवाद और वादी किसी के नहीं इसलिए वह चाल में फसेंगे लगता नहीं है।

## एसईसीएल से होगा वाटर एटीएम का सुधार... चहते को मिला काम

वैसे बताया जा रहा है कि वाटर एटीएम जो पंचायत का था और जिसकी जिम्मेदारी मरम्मत की पंचायत की थी वह अब एसईसीएल द्वारा मरम्मत कराया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि वाटर एटीएम को श्रमिक नेता चाहते तो पंचायत मद से सुधरेगा लेते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया वहीं अब जब एसईसीएल ने उसका जिम्मा लिया है तो वहां भी श्रमिक नेता की गिद्ध नजर जा पड़ी है और अपने ही चहते को श्रमिक नेता ने मरम्मत कार्य दिला दिया है। सूत्रों की माने तो तय कर्मशान का इसमें भी खेल है।

## प्रकरण के अज्ञात आरोपी को सर्वमंगला पुलिस ने किया गिरफ्तार

-संवाददाता-

कोरबा, 10 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)।

जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा क्षेत्र में हो रहे डीजल,कोयला, लोहा चोरी, जुआ सट्टा आबकारी एवं अवैध कबाड के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के लिये दिये गये निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस चौहान व नगर पुलिस अधीक्षक विमल कुमार पाठक,रही,रूपक शर्मा थाना प्रभारी कुसमुंडा के मार्गदर्शन में चोरी के प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त होने पर परिपालन में प्रार्थी संजय कुमार दुबे पिता स्व. नागेंद्र नाथ दुबे उम्र 49 वर्ष साकिन प्रधान सुरक्षा प्रहरी महाप्रबंधक कार्यालय SECL कुसमुंडा जिला कोरबा द्वारा दिनांक 4-5/11/2024 के दरम्यान रात को अज्ञात आरोपी के द्वारा 03 नम्बर वर्क शॉप SECL कुसमुंडा खदान से 04 नग लोहे का चैनल, 08 नग लोहे का प्लेट वजन 06 किलो को चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर पुलिस सहायता केन्द्र सर्वमंगला में अपराध क्रमांक 361/24 धारा 303(2) BNS दर्ज कर अज्ञात आरोपी की सरगमी से पतासाजी कि जा रही थी। पतासाजी दौरान आरोपी राजू साहू उर्फ प्रकाश साहू पिता भागवत प्रसाद साहू उम्र 32 साल साकिन सर्वमंगला नगर बरमपुर पुलिस सहा. के. सर्वमंगला थाना कुसमुंडा जिला कोरबा छ.ग. से पृच्छाछ करने पर घटना दिनांक 4-5/11/2024 को 03 नम्बर वर्क शॉप स्थल कुसमुंडा खदान से चोरी करना स्वीकार किया जिसके कब्जे से 04 नग लोहे का चैनल, 08 नग लोहे का प्लेट वजन 06 किलो कीमती 20000 रुपये को जमा कार्यवाही कर आरोपी को पुलिस सहा. के. सर्वमंगला के द्वारा माननीय न्यायालय कटघोरा में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।

## विधायक शकुंतला द्वारा धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित



-संवाददाता-

सूरजपुर, 10 नवम्बर 2024

(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार राज्य में 14 नवम्बर से शुरू होने वाले धान खरीदी की तैयारी के संबंध में प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोतें के द्वारा जनपद कार्यालय प्रतापपुर के सभाकक्ष में बैठक लेकर समीक्षा की गई, बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को धान खरीदी केन्द्र पर धान बेचने आने वाले किसानों के लिए समुचित व्यवस्था करते हुए सम्मान किसानों की धान खरीदी करने का निर्देश

दिया गया। विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोतें द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार प्रतापपुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सर्व आदिम जाति सेवा सहकारी समिति प्रबंधक प्रतापपुर जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक, आपरेंट, मंडी सचिव, खाद्य निरीक्षक से समिति वार धान खरीदी के तैयारी के संबंध में जानकारी ली गई। समिति वार बारदाना की उपलब्धता सुगली, तोल मशीन, नमी मापक यंत्र, स्टेन्सील, तारपोलिन कवर की उपलब्धता, साफ सफाई, बिजली, पेयजल, किसानों की बैठक व्यवस्था, टोकन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली गई। विधायक

द्वारा सभी समिति प्रबंधको एवं शाखा प्रबंधक को निर्देशित किया की धान विक्रेता कृषकों के साथ भेद भाव की शिकायत प्राप्त नहीं होना चाहिए सभी से सम्मानपूर्वक व्यवहार हो। किसी कृषक को अपने धान के पैसे प्राप्त करने हेतु बैंक में अधिक बिलंब न हो। शाखा प्रबंधक को किसानों के ए टी एम कार्ड अधिक से अधिक बनाये जाने हेतु समिति वार ग्रामों में शिविर लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सभी किसानों के धान विक्रय एवं धान के पैसे का भुगतान हेतु समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही राजस्व अमलों को अवैध तरीको से धान के आवक

रोकने हेतु बौरयर लगाने, छपा मार कार्यवाही करने एवं अवैध धान पाये जाने पर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त समीक्षा बैठक में श्रीमती ललिता भगत एसडीएम प्रतापपुर, श्री सालिक राम गुप्ता तहसीलदार प्रतापपुर, श्री मुकेश दास नायब तहसीलदार प्रतापपुर, श्रीमती सरिता राजवाडे नायब तहसीलदार प्रतापपुर, श्री संजय कुमार शर्मा नायब तहसीलदार डंडकरवा, श्री शिवशंकर यादव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रतापपुर, श्री शशि जायसवाल खाद्य निरीक्षक प्रतापपुर, श्री रामधनी भगत मंडी सचिव प्रतापपुर इत्यादि उपस्थित रहे।

## बालको खेलों को बढ़ावा देने के लिए सदैव रहा अग्रणी



-संवाददाता-

कोरबा, 10 नवम्बर 2024

(घटती-घटना)।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) धातु उत्पादन के साथ, शुरूआत से ही जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करता रहा है। औद्योगिक विकास के साथ ही खेल क्षेत्र में भी कंपनी का समुद्ध इतिहास रहा है। युवाओं को खेल से जोड़ने में कंपनी ने

प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी क्लब ने 1976 में आउटडोर तथा इनडोर खेल का आयोजन शुरू किया। इसी साल अप्रैल कमेटी द्वारा चाचा नेहरू के जन्मदिन पर त्रिटंगी (दो लोगों के पैरों को मिलाकर) खेल का आरंभ किया। लेडिज क्लब 1976 में ईंधन बचत के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साईकिल रिक्शा रेंस को आयोजन किया।

## कोर्ट मोहर्रियों की बैठक में एसएसपी के कड़े निर्देश...समंस-वारंटों की हो तामिली



-संवाददाता-

सूरजपुर, 10 नवम्बर 2024

(घटती-घटना)।

फरियादी, पीडित व्यक्ति को सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि माननीय न्यायालयों द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर शत-प्रतिशत थाना-चौकी के माध्यम से सुनिश्चित हो। कोर्ट मोहर्रियों, थाना-

चौकी से न्यायालयीन कार्य हेतु जाने वाले कर्मचारी तथा थाना में समंस-वारंट के संधारण करने वालों के बीच आपसी सामान्य बनकर कार्य करने के उद्देश्य को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने रविवार, 10 नवम्बर 2024 को तामीली समय पर शत-प्रतिशत थाना-चौकी के मोहर्रियों, समंस वारंट के कार्य करने वाले



जवानों की बैठक ली। इस दौरान एसएसपी सूरजपुर ने कोर्ट मोहर्रियों को कहा कि माननीय न्यायालय के द्वारा जिस तारीख को समंस-वारंट जारी किए जाते हैं, उन्हें उसी दिन संबंधित थाना-चौकी को भेजी जावे ताकि उसकी तामीली शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो सके। थाना चौकी में न्यायालयीन कार्य हेतु जाने वाले कर्मचारी से इस बावत सामंजस्य स्थापित करें।

उन्होंने कहा कि आपके सजग रहकर कार्य करने से समंस-वारंट की तामीली सही समय होगी और फरियादियों को न्यायालय से जल्द न्याय मिलेगा। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, डीएसपी मुख्यालय महलक्ष्मी कुलदीप, स्टेशन अखिलेश सिंह, रीडर अरविन्द्र प्रसाद सहित सभी कोर्ट मोहर्रि सहित अन्य आरक्षकगण मौजूद रहे।



